अमन चौधरी जे. के समक्ष

दीपिंदर मनु बेदी-याचिकाकर्ता

बनाम

प्रोविडेंट फंड इंस्पेक्टर (एनफोर्समेंट ऑफिसर)-प्रतिवादी

2019 का सी. आर. आर. सं. 867 (ओ एंड एम)

31 अक्टूबर, 2022

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952-एस.एस. 6, 14 (1), 14 (1ए), 14ए (1)-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संविधि की खंड 14 (1क) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराए गए याचिकाकर्ता को 8 महीने के कठोर कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। रुपए 6000/- जुर्माना और एक महीने के लिए आर. आई. से गुजरने के लिए जुर्माने के भुगतान में चूक-अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपील खारिज कर दी गई, हालांकि जुर्माने के साथ सजा घटाकर 6 महीने कर दी गई-वर्तमान पुनरीक्षण याचिका में अधिनियम की खंड 14 (1क) और 14 (ख) के प्रावधान के तहत अदालत की शक्ति के आधार पर सजा की मात्रा को अधिनियम द्वारा निर्धारित अवधि से कम करने की मांग की गई है-लंबे मुकदमे के आधार और परिवार का एकमात्र कमाने वाला होने के कारण-पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई-सजा को याचिकाकर्ता द्वारा पहले से गुजर चुकी अवधि तक कम कर दिया गया, जो जुर्माने के भुगतान के अधीन है।

यह मानते हुए कि भविष्य निधि प्राधिकरणों द्वारा मांगी गई भविष्य निधि बकाया की पूरी राशि, याचिकाकर्ता द्वारा पहले ही जमा कर दी गई थी, जैसा कि उपरोक्त तथ्य नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा भी देखा गया था, सी. डब्ल्यू. 1, पी. सी. ठाकुर की प्रतिपरीक्षा दिनांक 08.08.2017 का संदर्भ देते हुए, "अभियुक्त पहले ही राशि जमा कर चुका है जो वर्तमान शिकायत का विषय है।मैंने अपने लेखा खंड से इस तथ्य को सत्यापित किया है। अब राशि को लेकर कोई विवाद नहीं है।" याचिकाकर्ता इस अदालत द्वारा अपनी सजा के निलंबन से पहले ही 1 महीने और 9 दिनों की वास्तविक सजा काट चुका है। वे 45 वर्ष के हैं और पिछले 10 वर्षों से लंबे मुकदमे की पीड़ा का सामना कर रहे हैं। वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है, जिसमें पत्नी, बच्चे और एक विधवा माँ शामिल हैं। एक व्यापक परिप्रेक्ष्य पर विचार करते हुए, यह न्यायालय इसे एक ऐसा मामला मानता है जो कारावास के बदले जुर्माना लगाने की कम सजा देता है।

(पैरा 19)

आगे यह अभिनिर्धारित किया कि तथ्यों की विशिष्टता और वर्तमान मामले की परिस्थितियों और पूर्व निर्दिष्ट निर्णयों, पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है, जबकि सजा को याचिकाकर्ता द्वारा पहले से गुजर चुकी अवधि तक कम कर दिया जाता है, जो जुर्माने के भुगतान के अधीन है।

(पैरा 20)

सभी मामलों में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राहुल शर्मा।

सभी मामलों में प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता संजय तंगरी।

अमन चौधरी, जे.

(1) इस निर्णय के माध्यम से, 22 याचिकाओं के एक समूह का एक साथ निपटान किया जाएगा, क्योंकि कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न शामिल हैं।तथ्य सी. आर. आर.-867-2019 से लिए जा रहे हैं।

(2) वर्तमान याचिका में विद्वत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंडीगढ़ द्वारा पारित दोषी ठहराए जाने के फैसले और सजा के आदेश को रद्द करने और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ द्वारा दिए गए फैसले को भी रद्द करने की प्रार्थना की गई है।

(3) वास्तव में, तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता मैसर्स पॉट्स एंड प्लांट्स, मकान नंबर 530 सेक्टर 10, चंडीगढ़ के एक प्रतिष्ठान का प्रभारी था और इसके व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार था।इसलिए, उन्हें महीने के अंत के 15 दिनों के भीतर, प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के संबंध में हर महीने कर्मचारी भविष्य निधि का योगदान जमा करना आवश्यक था।लेकिन कई अनुरोधों और अनुनय के बावजूद, उन्होंने इसे जमा नहीं किया, जिसके कारण, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब द्वारा दिनांकित 16.7.2012 आदेश द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद, याचिकाकर्ता के खिलाफ कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 30,38 और 76 (डी) के साथ पठित ई. पी. एफ. एम. पी. अधिनियम की धारा 6,14 (1), 14 (1ए) और 14ए (1) के तहत दिनांकित 20.7.2012 शिकायत दर्ज की गई थी।विद्वत विचारण न्यायालय ने दिनांक 20.7.2012 के आदेश के माध्यम से अभियुक्त-याचिकाकर्ता को मुकदमे का सामना करने के लिए समन करके बुलाया, जिसमें उसके खिलाफ ई. पी. एफ. एम. पी. अधिनियम की धारा 14ए (1) के साथ 14 (1ए) और 14 (1) के तहत आरोप बनाए गए थे, जिसमें उसने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का दावा किया।

(4) अपना मामला साबित करने के लिए, शिकायतकर्ता ने सी. डब्ल्यू.-1 पी. सी. ठाकुर, प्रवर्तन अधिकारी से पूछताछ की।शिकायतकर्ता के साक्ष्य को बंद करने पर, आरोपी-याचिकाकर्ता का बयान खंड 313 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत दर्ज किया गया था। सभी आपत्तिजनक सामग्री को आरोपी के सामने रखा गया था।उन्होंने आरोपों का खंडन किया।बचाव में, उन्होंने डी. एल. एफ. इंफो के साइट प्रमुख, डी. डब्ल्यू. 1 अभिषेक शर्मा से पूछताछ की।सिटी डेवलपर्स, डीडब्ल्यू 2 गौरव वालिया, डीडब्ल्यू 3 राजेश कुमार और डीडब्ल्यू 4 विशाल सिंह।

(5) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंडीगढ़ ने दिनांक 30.8.2017 के फैसले के माध्यम से याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया और उसे कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (संक्षेप में 'ई. पी.

एफ. एम. पी. अधिनियम') की खंड 14ए (1ए) के साथ पठित खंड 14ए (1) के तहत दंडनीय अपराध के लिए 8 महीने के कठोर कारावास और रुपये 6000/- के जुर्माने का भुगतान करने की सजा सुनाई और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर उसे एक महीने के लिए आर. आई. से गुजरना पड़ा।

(6) उपरोक्त निर्णय/आदेश के खिलाफ पीड़ित, याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ के समक्ष अपील दायर की थी, जिसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ द्वारा दिनांक 28.3.2019 के फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।हालाँकि, सजा के आदेश को इस हद तक संशोधित किया गया था कि याचिकाकर्ता की सजा की अवधि 8 महीने से घटाकर 6 महीने कर दी गई थी, हालाँकि जुर्माना बरकरार रखने का आदेश दिया गया था।

(7) इसलिए, वर्तमान पुनरीक्षण याचिकाएँ।

(8) याचिकाकर्ता का विद्वान अधिवक्ता, शुरू में ही दोषसिद्धि की चुनौती को छोड़ देता है और केवल सजा की मात्रा के संबंध में वर्तमान याचिकाओं में अपनी प्रार्थना को सीमित करता है।इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता का तर्क होगा कि याचिकाकर्ता, जो 45 वर्ष का है, अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है जिसमें पत्नी, बच्चे और एक विधवा माँ शामिल हैं। वह पहला अपराधी है, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। याचिकाकर्ता पिछले 10 वर्षों से लंबे मुकदमे की पीड़ा का सामना कर रहा है। इसके बाद वह तर्क देता है कि अपराध करने का मुख्य कारण मामले में स्पष्ट रूप से गायब है, क्योंकि याचिकाकर्ता की इकाई को 01.05.2008 को बंद कर दिया गया था, जिसे देखते हुए, उसने स्वीकार किया था, न तो कर्मचारियों से कोई योगदान काटा था और न ही उसे करने की आवश्यकता थी, क्योंकि उसके प्रतिष्ठान के बंद होने के बाद से कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा था।विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान आपराधिक कार्यवाही विचाराधीनता रहने के दौरान, याचिकाकर्ता ने भविष्य निधि प्राधिकरणों द्वारा मांगी गई भविष्य निधि बकाया की पूरी राशि के रूप में पहले ही रु. 6,31,421 की राशि जमा कर दी है।उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता इस अदालत द्वारा अपनी सजा के निलंबन से पहले ही 1 महीने और 9 दिनों की वास्तविक सजा काट चुका है। इसलिए वह प्रार्थना करता है कि ई. पी. एफ. एम. पी. अधिनियम की खंड 14 (1क) और 14 (1ख) के प्रावधान के आधार पर, इस न्यायालय को अधिनियम द्वारा निर्धारित सजा से कम सजा देने की शक्ति है।अपने निवेदन को पुष्ट करने के लिए, विद्वान अधिवक्ता भविष्य निधि फंड इंस्पेक्टर, लुधियाना बनाम हरजिंदर सिंह निदेशक, हैकब्रिजहेविटिक एंड ईसन लिमिटेड बनाम भविष्य निधि निरीक्षक, छूट-III-प्रभाग।(मद्रास), भविष्य निधि आयुक्त बनाम बी. एल. धचोलिया एम. आर. जोसेफ, प्रवर्तन अधिकारी, ई. पी. एफ. बनाम जॉन मेनेजेस जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कम करने वाली परिस्थितियों को देखते हुए कारावास के बदले जुर्माना लगाया जा सकता है।

(9) इसके विपरीत, याचिका का विरोध करते हुए, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि नीचे दिए गए विद्वान न्यायालयों ने मामले के हर पहलू की सराहना करने के बाद याचिकाकर्ता को सही तरीके से दोषी ठहराया है और सजा सुनाई है, इस प्रकार वह वर्तमान याचिकाओं को खारिज करने के लिए प्रार्थना करता है।

(10) जहाँ तक याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता की प्रतिबंधित प्रार्थना का संबंध है, उन्होंने तर्क दिया है कि अपील न्यायालय ने सजा में कमी के संबंध में याचिकाकर्ता की याचिकाओं पर पहले ही विचार कर लिया है और प्रत्येक मामले में इसे 8 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया है, जो अधिनियम द्वारा निर्धारित न्यूनतम सजा है।इसलिए, उन्होंने अनुरोध किया कि याचिकाकर्ता को दी गई सजा को बरकरार रखा जाना चाहिए।

(11) सुना है।

(12) हालाँकि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि को चुनौती नहीं दी है, हालाँकि, नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों से, यह स्पष्ट है कि निचली अदालत ने याचिकाकर्ता को साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया था और सजा सुनाई थी।अपील न्यायालय ने अधिनियम के उद्देश्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दोषसिद्धि के उक्त निर्णय की पुष्टि की थी, जबकि याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए सजा के आदेश को आठ महीने से घटाकर छह महीने कर दिया गया था।यह न्यायालय निचली न्यायालयों द्वारा पारित विवादित निर्णयों/आदेशों में कोई अवैधता या विकृति नहीं पाता है।

(13) जहां तक याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना का संबंध है कि सजा की मात्रा में कमी का संबंध है, सबसे पहले, ई. पी. एफ. एम. पी. अधिनियम की खंड 14 (1 क) और खंड 14 (1 ख) का उल्लेख करना उचित है, जो इस प्रकार हैः-

1 1983 (2) आर. सी. आर. (सी. आर. एल.) 131 (पी एंड एच)

2 1992 सी. आर. आई. एल. जे. 303

3 1985(2) एल. एल. एन. 447 (डेल)

4 आई. एल. आर. 2003 (4) कर 4525

14 दंड.—

(1) जो कोई भी, इस अधिनियम योजना, पेंशन योजना या बीमा योजना के तहत अपने द्वारा किए जाने वाले किसी भी भुगतान से बचने के उद्देश्य से या किसी अन्य व्यक्ति को इस तरह के भुगतान से बचने में सक्षम बनाने के लिए, जानबूझकर कोई गलत बयान या गलत अभ्यावेदन देता है या बनाता है, वह एक वर्ष, या पांच हजार रुपये के जुर्माने या दोनों तक की अवधि के कारावास से दंडनीय होगा।

(1 क) एक नियोक्ता जो खंड 6 या खंड 17 की उप-खंड (3) के खंड (क) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, या अनुपालन करने में चूक करता है, जहां तक यह निरीक्षण शुल्क के भुगतान से संबंधित है,

या योजना के पैराग्राफ 38 जहां तक यह प्रशासनिक शुल्क के भुगतान से संबंधित है, वह कारावास से दंडनीय होगा जो 21 [तीन साल] तक की अवधि के लिए हो सकता है, लेकिन -

(क) जो कर्मचारियों के अंशदान के भुगतान में चूक के मामले मे [एक वर्ष और दस हजार रुपये के जुर्माने] से कम नहीं होगा, जिसे नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के वेतन से काट लिया गया है।

(ख) जो छह महीने से कम नहीं होगा और किसी अन्य मामले में पाँच हजार रुपये का जुर्माना होगा। बशर्ते कि न्यायालय, निर्णय में अभिलिखित किए जाने वाले किसी भी पर्याप्त और विशेष कारणों के लिए, कम अवधि के लिए कारावास की सजा दे सकता है।

(1 ख) एक नियोक्ता जो खंड 6 सी, या खंड 17 की उप-खंड (3 क) के खंड (क) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उनका पालन करने में चूक करता है, जहां तक वह निरीक्षण शुल्क के भुगतान से संबंधित है, वह 27 [एक वर्ष] तक की अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, लेकिन जो 28 [छह महीने] से कम नहीं होगा और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा जो 29 [पांच हजार रुपये] तक बढ़ सकता है। बशर्ते कि न्यायालय, निर्णय में दर्ज किए जाने वाले किसी भी पर्याप्त और विशेष कारणों के लिए, कम अवधि के लिए कारावास की सजा लगा सकता है।

(14) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए की गई प्रार्थना के संबंध में इस न्यायालय के समक्ष उद्धृत निर्णयों का संदर्भ समीचीन हो सकता है।

दीपिंदर मनु बेदी बनाम प्रोविडेंट फंड इंस्पेक्टर 1569

(प्रवर्तन अधिकारी) (अमन चौधरी, जे.)

(15) हरजिंदर सिंह निदेशक (उपरोक्त) के मामले में, मुकदमा अदालत ने आरोपी पर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की खंड 14 (1) (क) के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा नहीं लगाई थी, इसके बजाय, आरोपी को रुपये 1000/- का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई थी- भरोसा करते हुए, जिसे उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था।वर्तमान मामले से संबंधित पैरा इस प्रकार हैः

“बशर्ते कि न्यायालय, निर्णय में दर्ज किए जाने वाले किसी भी पर्याप्त और विशेष कारणों के लिए, केवल कारावास के बदले में कम अवधि के लिए कारावास या जुर्माने की सजा दे सकता है।” तदनुसार, इस न्यायालय ने भविष्य निधि निरीक्षक, लुधियाना द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए कहाः

“5. "पर्याप्त और विशेष कारण" अभिव्यक्ति का उपयोग अक्सर अब विधानमंडल द्वारा किया जाता है, जहां यह सजा के मामले में न्यायालय के विवेक को सीमित करने या बाधित करने के लिए कदम उठाता है।इसके बाद न्यायालय को कुछ विवेक के साथ छोड़ दिया जाता है, लेकिन विधायिका द्वारा खुले रखे गए सीमित क्षेत्र के भीतर, लेकिन मेरे दिमाग में सीमित क्षेत्र की सीमा समान नहीं हो सकती है।प्रत्येक कानून में, जिसमें उपरोक्त अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है, यह अधिनियम की योजना से रंग लेता है, जिस उद्देश्य को सुधारने की मांग की जाती है।उदाहरण के लिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रिश्वत और भ्रष्टाचार की अधिक प्रभावी रोकथाम के लिए एक अधिनियम है जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है।

इसी तरह खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम अपनी प्रस्तावना में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए प्रावधान करने वाला एक अधिनियम है।ये कानून प्रकृति में निवारक हैं और भ्रष्टाचार और खाद्य मिलावट के कुकर्मों पर रोक लगाने से संबंधित हैं।समानान्तर वे उद्देश्य हैं जो दोनों कानूनों में प्राप्त किए जाने की मांग की गई है, एक सार्वजनिक सेवा को स्वच्छ रखने के लिए और दूसरा खाद्य भोजन को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए; दोनों एक स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक हैं।

हालाँकि, वर्तमान में जिस अधिनियम पर विचार किया जा रहा है, वह कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की स्थापना के लिए एक अधिनियम है।जैसा कि इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि इसमें कुछ भी निवारक नहीं है। बल्कि समय पर पूरा करने के लिए एक सकारात्मक दिशा है। जो खंड 14 और अन्य खंडो में दिए गए दंड की पीड़ा पर दायित्व है।दूसरे शब्दों में वर्तमान अधिनियम कहता है; "यह काम करो", जबकि पूर्व में वर्णित अन्य कानूनों में कहा गया है कि "ऐसा मत करो"।एक का दृष्टिकोण सकारात्मक है जबकि दूसरे का दृष्टिकोण नकारात्मक है।यह उन कारणों में से एक है जो मेरे लिए इस विचार को रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि यह वर्तमान में सलाह देता है, कि वर्तमान अधिनियम के संदर्भ में "पर्याप्त और विशेष कारण" अभिव्यक्ति अभियुक्त के लिए एकल नहीं हो सकती है और मामले के तथ्य और परिस्थितियां भी एकल नहीं हो सकती हैं।संदर्भ में "पर्याप्त और विशेष कारण" शब्दों के विरोधाभासी, जैसा कि मुझे लगता है, कुल विलक्षणता और कुल व्यापकता के बीच कहीं न कहीं टिका होगा, और निश्चित रूप से उनका परिणाम कुल विलक्षणता और कुल व्यापकता के बीच कहीं न कहीं टिका होगा, और निश्चित रूप से उनका परिणाम मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के लिए विशेष होगा।

6. वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस लौटते हुए, अदालत ने न केवल इस बात को ध्यान में रखा कि भविष्य निधि का भुगतान किया गया था, हालांकि देर से किया गया था, बल्कि आरोपी ने ऐसा करने की पेशकश करते समय कोई सबूत भी पेश नहीं किया था और गुण-दोष के आधार पर मामले को नहीं लड़ा था।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में एक छोटी सी दलील सौदेबाजी सामने आती है।और यदि न्यायालय, अभियुक्त द्वारा अपनाए गए निष्पक्ष रुख पर उसे उदार व्यवहार देने का विकल्प चुनता है तो जाहिर है कि यह विशेष मामले के अभियुक्त के लिए विशेष और पर्याप्त होता है।भविष्य निधि रखरखाव की अवधारणा के संदर्भ में एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने पर, मुझे नहीं लगता कि केवल जुर्माने की सजा पारित करने में ट्रायल मजिस्ट्रेट किसी भी तरह से अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक था या इस मामले या आरोपी के बारे में कुछ भी विशेष नहीं था जो कम सजा की गारंटी नहीं देता था।इस प्रकार, मेरा मानना है कि विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश में संशोधन में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।"

(16) हैकब्रिजहेविटिक एंड ईसन लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:"यद्यपि यह तथ्य कि कर्मचारियों के भविष्य निधि योगदान और अन्य देय राशि के भुगतान के लिए दायित्वों और देनदारियों का पूरी तरह से याचिकाकर्ताओं द्वारा भविष्य निधि आयुक्त के साथ किए गए समझौते या व्यवस्था के अनुसार निर्वहन किया गया था, हो सकता है कि स्वयं उन्हें 1952 के

अधिनियम की खंड 14 के प्रभावों से उत्पन्न दंडात्मक परिणामों से दोषमुक्त करता है, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसी परिस्थिति को निचली अदालत द्वारा ध्यान में रखी जाने वाली एक कम करने वाली या सुधार करने वाली परिस्थिति के रूप में बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता है, यदि यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि याचिकाकर्ता सजा देने के मामले में प्रस्तुत साक्ष्य पर दोषी हैं।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सच है कि 1952 के अधिनियम की खंड 14 के तहत कर्मचारियों के योगदान के भुगतान में चूक के मामले में न्यूनतम सजा तीन महीने है। इसके तहत एक नियम भी जोड़ा गया है, जो अदालत को निर्णय में दर्ज किए जाने वाले विशेष कारणों के लिए, कम अवधि के लिए कारावास की सजा या केवल कारावास के बदले जुर्माने की सजा देने की शक्ति देता है।याचिकाकर्ताओं के मामले पर सजा देने के मामले में बहुत नरमी से विचार करने के लिए विशेष कारणों की अधिकता को कम करने वाली परिस्थितियों के रूप में माने जाने से बेहतर मामला नहीं हो सकता है, केवल नाममात्र के जुर्माने के अधिरोपण के अर्थ में यदि वे दोषी पाए जाते हैं।"

दीपेंद्र मनु बेदी बनाम प्रोविडेंट फंड इंस्पेक्टर 1571

(प्रवर्तन अधिकारी) (अमन चौधरी, जे.)

(17) बी. एल. धाचोलिया (उपरोक्त) के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क यह है कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रतिवादी संख्या 1 को उप-न्यूनतम सजा देने में उचित नहीं था।खंड 14 (1ए) के तहत, योजना की खंड 6 और अनुच्छेद 38 के प्रावधानों का पालन करने में चूक सहित अधिनियम का उल्लंघन या प्रावधान छह महीने तक की अवधि के लिए कारावास के लिए दंडनीय होगा; लेकिन यह कर्मचारियों के योगदान के भुगतान में चूक के मामले में तीन महीने से कम नहीं होगा, जिसे नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के वेतन से काट लिया गया है।इसके अलावा उसे जुर्माने की सजा भी हो सकती है।तथापि, उक्त उप-धारा में एक परन्तुक है जो न्यायालय को, निर्णय में अभिलिखित किए जाने वाले किसी भी पर्याप्त और विशेष कारण के लिए, कम अवधि के लिए कारावास या केवल कारावास के बदले जुर्माने की सजा देने का अधिकार देता है।विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने, तत्काल मामले में, केवल जुर्माने की सजा देने का कारण दिया है। उन्होंने देखा है कि वे 2 जनवरी, 1976 से प्रभावी कंपनी और उस से पहले नहीं इन मामलों के लिए जिम्मेदार साबित हुए थे। विचाराधीन जमा राशि 1 जनवरी, 1976 को भी जमा की जा सकती थी, हालांकि इसकी अंतिम तिथि 15 जनवरी, 1976 थी।इसलिए, किसी भी मामले में, यह जांचना उनकी जिम्मेदारी थी कि भविष्य निधि में योगदान विधिवत किया गया है या नहीं।इसलिए इस विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को घटाकर केवल दोनों मामलों में से प्रत्येक में 100 रुपये का जुर्माना कर दिया।मुझे नहीं लगता कि विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा न्यूनतम सजा देने के लिए दिए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।"

(18) इसी तरह, जॉन मेनेजेस (उपरोक्त) के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"16. जहाँ तक सजा का संबंध है, विद्वान वकील को सुनें। यह न्यायालय के संज्ञान में लाया जाता है कि बाद में अभियुक्त ने अंशदान राशि का भुगतान कर दिया है और यह एक विलंबित भुगतान है। इसलिए, विद्वान वकील प्रस्तुत करता है कि चूंकि कार्यवाही वर्ष 1989 की है, इसलिए एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है और आगे की कार्यवाही को हटा दिया जा सकता है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि योगदान राशि का भुगतान बाद में किया जाता है और यह एक विलंबित भुगतान है।

17. विद्वान वकील की दलीलों पर विचार करते हुए और एडोनी कॉटन मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम क्षेत्रीय प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और ओ. आर. एस., 1996 एस. सी. सी. (एल. और एस. 201) मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में भी विलंबित भुगतान को देखते हुए और चूंकि कार्यवाही वर्ष 1989 की है, मुझे लगता है कि कारावास की कोई सजा देने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं है। हालाँकि, अभियुक्त को Rs.50 का जुर्माना देने की सजा सुनाई जाती है-इन सभी 3 अपीलों में से प्रत्येक में।"

(19) जैसा कि याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि निर्विवाद रूप से, भविष्य निधि प्राधिकरणों द्वारा मांगी गई भविष्य निधि बकाया की पूरी राशि रुपए 6,31,421/- होने के कारण, याचिकाकर्ता द्वारा पहले ही जमा कर दी गई थी, क्योंकि उपरोक्त तथ्य नीचे की अदालतों द्वारा भी देखा गया था, सी. डब्ल्यू. 1, पी. सी. ठाकुर की दिनांकित 8.8.2017 की प्रतिपरीक्षा का संदर्भ देते हुए, "अभियुक्त पहले ही वह राशि जमा कर चुका है जो कि वर्तमान शिकायत का विषय है। मैंने अपने लेखा खंड से इस तथ्य को सत्यापित किया है। अब राशि को लेकर कोई विवाद नहीं है।" याचिकाकर्ता इस अदालत के अदश दिनाक 16.5.2019 द्वारा अपनी सजा के निलंबन से पहले ही 1 महीने और 9 दिनों की वास्तविक सजा काट चुका है। वे 45 वर्ष के हैं और पिछले 10 वर्षों से लंबे मुकदमे की पीड़ा का सामना कर रहे हैं। वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है, जिसमें पत्नी, बच्चे और एक विधवा माँ शामिल हैं।एक व्यापक परिप्रेक्ष्य पर विचार करते हुए, यह न्यायालय इसे एक ऐसा मामला मानता है जो कारावास के बदले जुर्माना लगाने की कम सजा देता है।

(20) वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और पूर्व निर्दिष्ट निर्णयों की विशिष्टता के आलोक में, पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है, जबकि सजा को याचिकाकर्ता द्वारा पहले से भुगती गई अवधि तक सजा को कम कर दिया जाता है, जो रुपये के जुर्माने के भुगतान के अधीन है। इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर भविष्य निधि प्राधिकरणों को रुपए 5,000/-भुगतान किआ जाना चाहिए। ऐसा न करने पर, इन सभी पुनरीक्षण याचिकाओं को इस न्यायालय को आगे कोई निर्देश दिए बिना खारिज कर दिया गया माना जाएगा।

(21) तदनुसार निपटाया गया।

(22) इस आदेश की फोटोकॉपी जुड़े हुए संबधित मामलों की फाइलों मे रखी जानी चाहिए।

दिव्या गुर्ने

गुलशन कुमार

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।